

मुख्य समाचार :-

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा – साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार की अगले पांच साल में पांच हजार साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना।
- चम्पावत, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच भूजल प्रबंधन समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी।
- राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज एक से उन्नीस वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कृषि नाशक दवा— एल्बैंडोजोल खिलाई गई।
- चमोली जिले में माँ नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा देवी नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही समर्पन।

संबोधन 01

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि देश में साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। पांच साल में लगभग पांच हजार साइबर कमांडोज़ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। उन्होंने सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल अंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी तीन आपराधिक कानूनों में देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। संदिग्ध पंजीकरण की आई4सी पहल को लेकर श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का साइबर संदिग्ध पंजीकरण भविष्य में अपराधों को रोकने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि आई4सी साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया।

इस अवसर पर श्री शाह ने साइबर अपराध के विरुद्ध संरक्षण की मुख्य पहल और राष्ट्र के लिए समर्पित साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केन्द्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने साइबर अपराध डेटा संग्रह के लिए एक मंच—वेब आधारित मॉड्यूल समन्वय, शेयरिंग, मैपिंग और एनालिटिक्स और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय टूल का शुभारंभ किया। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों का एक विंग स्थापित करने संबंधी साइबर कमांडो कार्यक्रम और केन्द्रीय पुलिस संगठन का भी शुभारंभ किया गया।

राज्य स्तरीय संचालन समिति गठन

राज्य के तीन जल संकटग्रस्त जिलों— चम्पावत, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच भूजल प्रबंधन के संबंध में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। यह समिति जल बजटिंग और अटल भूजल योजना के तहत किए जा रहे कामों की स्थानीय स्तर पर निगरानी करेगी। मुख्य सचिव राधा रत्नांजली ने राज्य स्तरीय संचालन समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। समिति में लघु सिचाई विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए पेयजल व स्वच्छता, शहरी विकास, पंचायती राज, सिचाई, ग्राम्य विकास विभाग और स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजूविनेशन प्राधिकरण (सारा) को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यक्रम की नियमित रूप से मासिक समीक्षा करने को कहा। उन्होंने नोडल विभाग को स्थानीय निकायों के स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स नामित करने और उनके प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। यह मास्टर ट्रेनर वाटर प्लान व बजटिंग बनाने में सहायता करेंगे। श्रीमती रत्नांजली ने जल संकटग्रस्त चम्पावत, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में अटल भूजल योजना के तहत कैच द रैन, अमृतसरोवर, सारा की गतिविधियों को भी शामिल करने को कहा है। अटल भूजल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से वर्तमान में संचालित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के बीच समन्वय के माध्यम से सामुदायिक नेतृत्व व भागीदारी से स्थायी भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।

पशु टीकाकरण कार्यक्रम

चम्पावत जिले में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने टीकाकरण मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत नब्बे हजार गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाना है, जिसके लिए जिले में 25 टीमों का गठन किया गया है। मुख्य

विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में 45 दिनों तक अभियान चलेगा, इसके लिए जिले में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन पहुंच गई है।

कृमि मुक्ति दिवस

प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर एक से उन्नीस वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कृमि नाशक दवा— एल्बोडजोल खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक स्वाति एस. भदौरिया ने बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कृमि संक्रमण के दुष्प्रभावों को समझाते हुए, सभी बच्चों को समय पर दवाइयां लेने और स्वच्छता की आदतों को अपनाने को कहा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग बच्चों व किशोर—किशोरियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य बीमारियां, संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 37 लाख से अधिक बच्चों और किशोर—किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवा खिलाने का लक्ष्य रख गया है।

आदेश

राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था और इसकी निगरानी, कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, फॉगिंग और सत्यापन कार्य अब उप नगर आयुक्त द्वारा किया जाएगा। अभी तक यह काम मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाता था। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने पद के मूल कार्य करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य विभाग से समन्वय, शहरी क्षेत्र में डेंगू—मलेरिया रोकथाम, सर्विलांस, स्वास्थ्य जोखिम आकलन आदि कार्य शामिल हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिलाधिकारी नगर निगम के सफाई कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कूड़ा उठान कार्यों और इसकी निगरानी में लचर व्यवस्था पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। यह सभी कार्य उप नगर आयुक्त का है, जबकि जिले में कई वर्षों से यह कार्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपने पद के अन्य कार्यों के साथ कर रहे थे, जिसको जिलाधिकारी ने अब बदल दिया है।

शिलान्यास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वे बार एसोसिएशन, देहरादून के नवीन भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के महेनजर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है और 9 नवंबर से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

लोकजात

चमोली जिले में पिछले एक पखवाडे से चल रही माँ नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा का नंदा सप्तमी के अवसर पर नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही समापन हो गया। उच्च हिमालयी बुग्यालों में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जागर के साथ हिमालय की अधिष्ठात्री देवी माँ नंदा को कैलाश के लिये विदा किया। अपनी ध्यान को विदा करते समय महिलाओं की आंखे अश्रुओं से छलछला गयी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने साथ लाये खाजा—चूड़ा, बिंदी, चूड़ी, ककड़ी, मुंगरी भी समौन के रूप में माँ नंदा को अर्पित किये। दूसरी ओर, बालपाटा बुग्याल में दशोली कुरुड़ की माँ नंदा डोली की पूजा अर्चना करके कैलाश के लिए विदा किया गया।

दुर्घटना

केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास मूसलाधार बारिश से कल हुए भूस्खलन में पांच लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल तथा पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया। तीन घायलों को बचाया गया है। मृतकों में तीन मध्यप्रदेश के, एक गुजरात से तथा एक नेपाल से हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

आस्था पथ

चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव, उत्तरकाशी में तांबाखाणी से उजेली लक्ष्येश्वर तक भागीरथी नदी के किनारे आस्था पथ का निर्माण प्रस्तावित है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस महत्वाकांक्षी योजना की अनुमानित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सिंचाई विभाग से तैयार कराकर शासन को भेज दी है। इसके लिए 60 करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है। जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि योजना को धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही बजट को स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष जून में भागीरथी के किनारे आस्था पथ निर्माण की घोषणा की थी।